जून 2021 ₹ 20

समाजवादी बुलेटिन

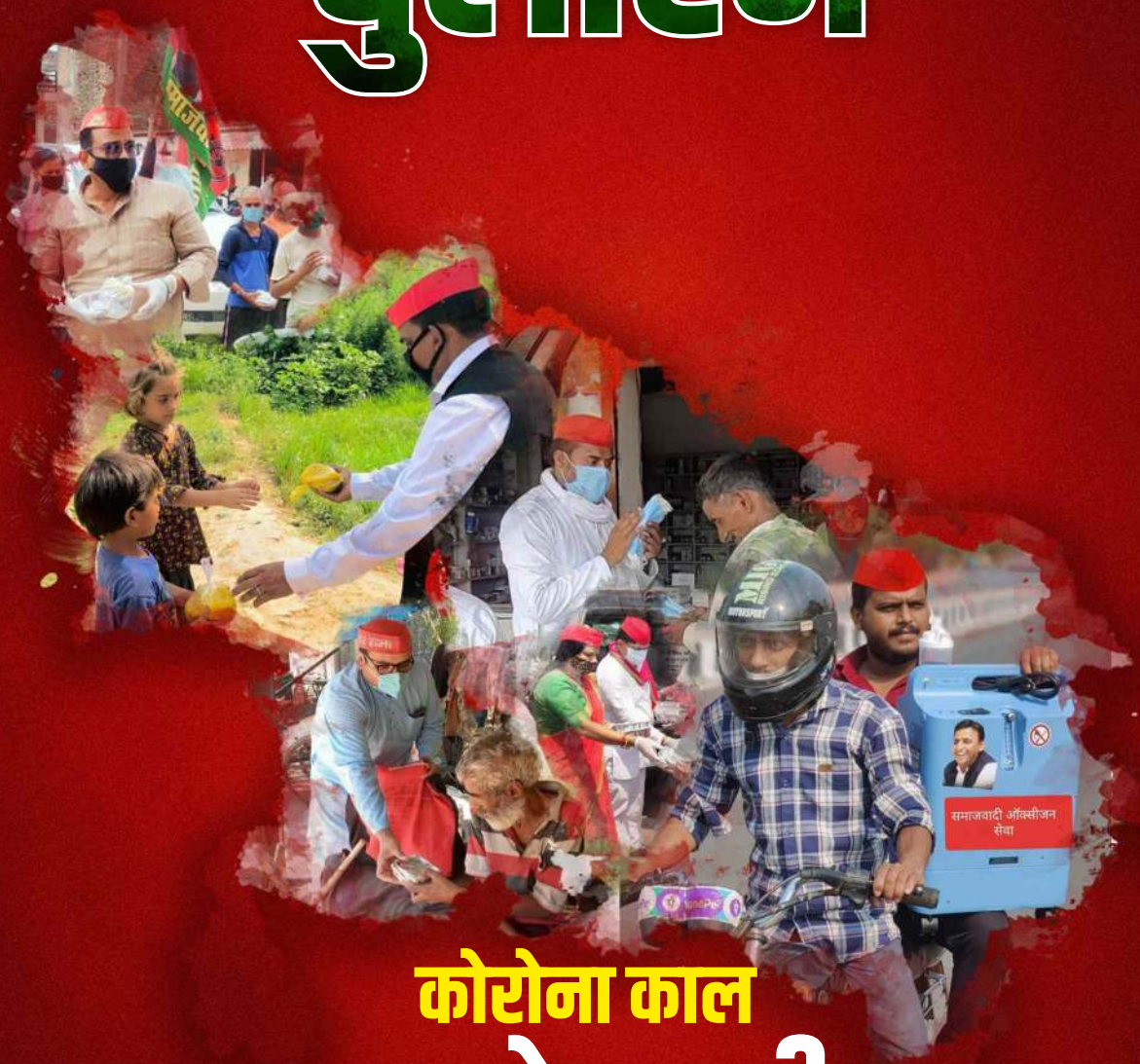

कोरोना काल
सबके साथी समाजवादी

06

राजकाज गोल, कुर्सी डांवाडोल 26 मोदी सरकार में वैक्सीन का हाल 20

R.N.I. No. 68832/97

समता और संपन्नता समाजवाद का मूल मंत्र है। समाज के सब लोगों को विकास के अवसर मिलें इसके लिए समाजवादियों को बढ़-चढ़कर काम करना होगा। सिर्फ नारे लगाने से समाजवाद नहीं आएगा, बल्कि समाजवादी सिद्धांतों को समझना और अपनाना होगा। समाजवादी विचारधारा को फैलाने की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी पर है।

मुलायम सिंह यादव
संस्थापक-संरक्षक, समाजवादी पार्टी

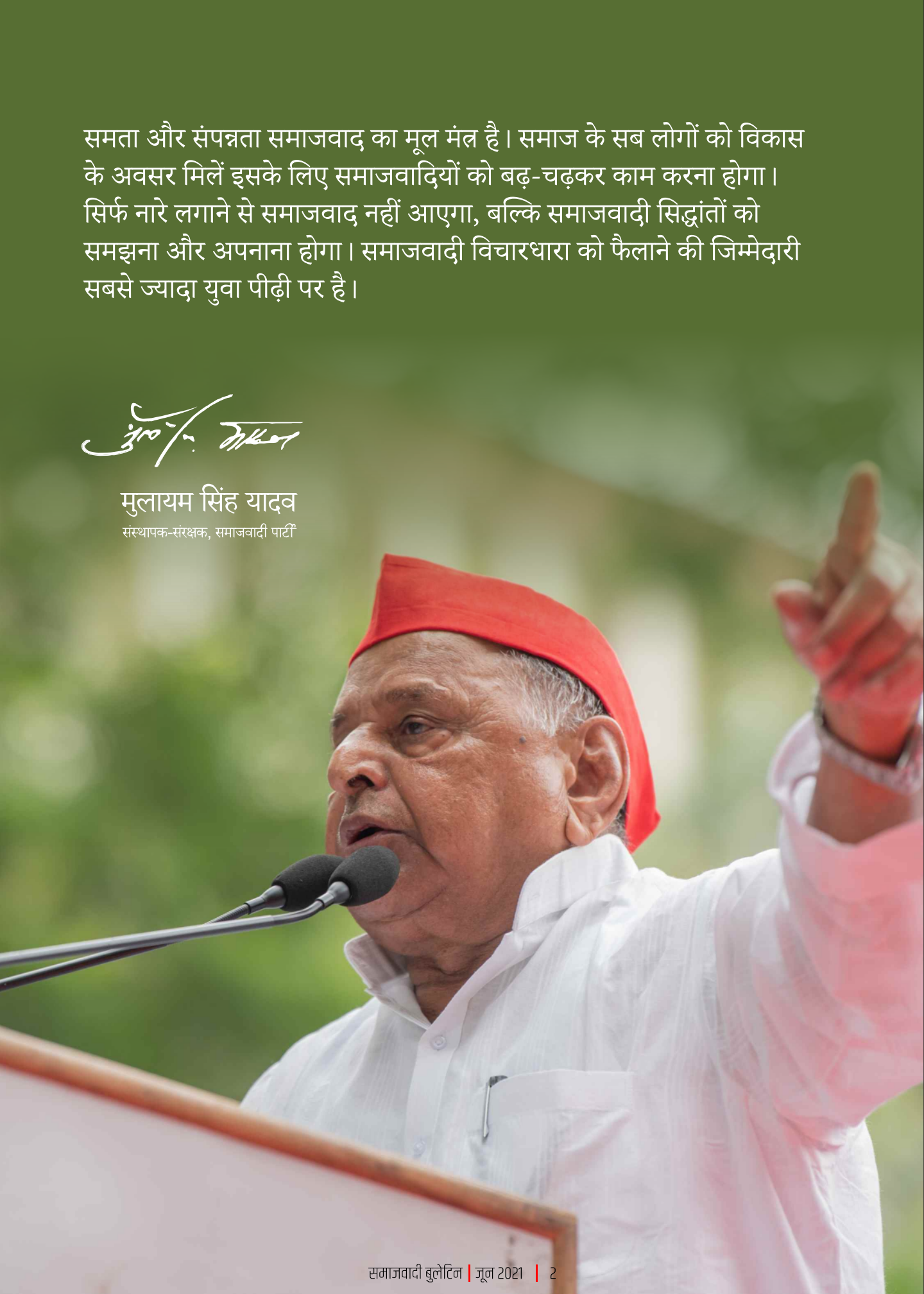

समाजवादी बुलेटिन

जून 2021

वर्ष 22 | संख्या 08

प्रिय पाठकों,

समाजवादी बुलेटिन आपकी अपनी पत्रिका है। इसके नए और बदले कलेवर को आप सबने सराहा है। आपका यह उत्साह वर्धन हमारी ऊर्जा है। कृपया अपनी राय से हमें अवगत कराते रहें। इसके लिए आप हमें नीचे दिए गए ईमेल पर लिख सकते हैं। कृपया अपना पूरा नाम, पता एवं मोबाइल नंबर जरूर दें। हम बुलेटिन को और बेहतर बनाने का प्रयास जारी रखेंगे। आपके संदेश की प्रतीक्षा रहेगी।

धन्यवाद

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक

प्रोफेसर रामगोपाल यादव

☎ 0522 - 2235454

samajwadibulletin19@gmail.com

bulletinsamajwadi@gmail.com

Mob:- 9598909095

/samajwadiparty

समाजवादी पार्टी के लिए

19, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ से प्रकाशित

आस्था प्रिंटर्स, गोमती नगर, लखनऊ से मुद्रित

R.N.I. No. 68832/97

अंदर

वैक्सीन पर भाजपा ने जनता को धोखे में रखा 22

06 कवर स्टोरी **सबके साथी, समाजवादी**

सबको टीका कवर स्टोरी 20

नीति न नीयत, असर फीका

21 जून से शुरू टीकाकरण का यह अभियान ही देश की जरूरत थी जिसे लागू करने में 5 महीने 5 दिन की देरी हुई है। इस देरी का खामियाजा पूरे देश ने भुगता है।

राजकाज गोल, कुर्सी डांवाडोल 26

सपा के प्रति बढ़ता जा रहा रूझान 28

लक्ष्मण निषाद के सिंघाड़े और अखिलेश जी की सदाशयता!

बुलेटिन ब्यूरो

जनपद रायबरेली के हरचंदपुर ब्लाक के लक्ष्मण निषाद के प्रति समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव का व्यवहार इस बात की बानगी है कि किसी गरीब के प्रति एक नेता का रवैया कैसा होना चाहिए। लक्ष्मण निषाद के प्रति श्री अखिलेश यादव का सदाशयता का यह भाव बीते करीब तीन वर्षों से निरंतर कायम है।

उत्तर प्रदेश में लक्ष्मण सरीखे हाशिए पर खड़े ऐसे लाखों लोग हैं जिनके प्रति श्री अखिलेश यादव का यही बर्ताव है और उनके व्यक्तित्व का यही पहलू उनकी अलग सकारात्मक छवि बनाता है। एक ऐसी शख्सियत जिनसे लोग उम्मीद करते हैं और वे निराश भी नहीं करते। उत्तर प्रदेश में गरीब कहीं हो उसे लगता है कि अखिलेश जी से ही राहत मिलेगी। प्रदेश भर में लाखों ऐसे हैं जिनको तहेदिल से यह विश्वास है।

श्री अखिलेश यादव एक ऐसी शख्सियत जिनसे लोग उम्मीद करते हैं और वे निराश भी नहीं करते। उत्तर प्रदेश में गरीब कहीं हो उसे लगता है कि अखिलेश जी से ही राहत मिलेगी। प्रदेश भर में लाखों ऐसे हैं जिनको तहेदिल से यह विश्वास है।

दरअसल जनपद रायबरेली के हरचंदपुर ब्लाक के लक्ष्मण निषाद अघौरा घाट में सिंघाड़े की खेती करते हैं। गत 14 दिसम्बर 2019 को जब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव उधर से गुजरे तो उन्होंने सिंघाड़ा इकट्ठा करते लक्ष्मण को पुकारा, पहले तो वह सकुचाए लेकिन जब आए तो अखिलेश जी इतनी आत्मीयता से उनसे मिले कि तब से लक्ष्मण उनसे तीन बार मिल चुके हैं। 3 जून 2021 को जब लक्ष्मण निषाद समाजवादी पार्टी के लखनऊ कार्यालय आए तो हमेशा की तरह श्री अखिलेश यादव उनसे गर्मजोशी से मिले।

पहली मुलाकात में सहमे लक्ष्मण से जब अखिलेश जी ने आत्मीयता से बात की तो उनका हौसला बढ़ा और कृतज्ञतावश उन्होंने चंद सिंघाड़े अखिलेश जी को भेंट कर दिए। उनकी मां कलावती भी एक दिन उत्सुकतावश अखिलेश जी से मिलीं। अब यह परिवार अखिलेश जी की दिन रात प्रशंसा करते थकता नहीं।

लक्ष्मण निषाद जिस क्षेत्र के हैं वहां वर्ष 2004 में श्री अखिलेश यादव ने जिस ऊबड़-खाबड़ सड़क पर साइकिल चलाई थी उसे उनकी सरकार में ही साल 2014 में पक्की बनाया गया था। बछरावां बाईपास के चुरवा बार्डर रैन से पश्चिम गांव तक अब सड़क बन जाने से तमाम गांव वालों को सुविधाएं मिल गई है।

लक्ष्मण का कहना है कि वही नहीं, गांव के तमाम लोग भी अब भाजपा सरकार से तंग आ गए हैं। कोरोना संक्रमण में भी किसी ने पूछा नहीं। उनके गांव में बीमारो को ठीक से इलाज नहीं मिला। लॉकडाउन के चलते उसका धंधा चौपट हो गया है। डेढ़ वर्ष से उसको कहीं से कोई मदद नहीं मिली। लक्ष्मण निषाद ने अखिलेश जी को बताया कि परेशानी के इन दिनो में उनकी सब्जी की फसल बर्बाद हो गई तो उन्होंने उसे जरूरतमंदों में बंटवा दिया। लक्ष्मण का कहना है कि स्वयं उन्हें और सब्जी के काश्तकारों को बस अखिलेश जी से ही उम्मीदें है। लिहाजा वह चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी भाजपा सरकार की विदाई हो और समाजवादी पार्टी की सरकार बने, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनें।

लक्ष्मण निषाद की अखिलेश जी से भेंट के अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्री राजेंद्र चौधरी तथा समाजवादी पार्टी रायबरेली के जिलाध्यक्ष ई. वीरेन्द्र यादव भी उपस्थित थे।

सबके साथी समाजवादी

कोरोना की दूसरी लहर में जब उत्तर प्रदेश बेतहाशा मौतों, लगातार जलती चिताओ एवं नदियों में उतराती लाशों का गवाह बन रहा था तब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता खामोशी से हर गांव-हर गली में प्रभावित लोगों की मदद में जुटे थे। समाजवादी रसोई के माध्यम से कोविड संक्रमित मरीजों एवं उनके तीमारदारों के लिए निःशुल्क भोजन, अस्पतालों में फल वितरण, गरीब बस्तियों में राशन सामग्री, मास्क, सेनेटाइजर वितरण, अनाथालयों में राहत पैकेट, सहित ऑक्सीजन सिलेंडर आपूर्ति व्यवस्था में समाजवादी पार्टी पूरे मनोयोग से कार्य करती रही है। कोविड प्रोटोकॉल नियमों का पालन करते हुए पूरे प्रदेश में मानवीय कार्य का समाजवादियों का यह सिलसिला निरंतर जारी है। समाज के सामने संकट की घड़ी में समाजवादियों के सेवा भाव एवं उसके वैचारिक पहलुओं पर पेश है ***डॉ. ऋचा सिंह*** *की* ***विशेष रिपोर्ट:***

कोविड-19 आपदा ने एक बार फिर से विचारधारा के प्रश्न को भारत समेत पूरे विश्व के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। आज तमाम राजनैतिक और सामाजिक चिंतक इस पर विचार करने को मजबूर हैं कि 'समाजवाद ही आपदा से लड़ने की एक मात्र व्यवस्था हो सकती है' क्योंकि समाजवाद के केंद्र में समाज होता है।

आपदा से लड़ने में सरकार के साथ-साथ समाज की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और जब सरकारी व्यवस्था फ़ेल हो जाती है तो सामाजिक व्यवस्था ही एकमात्र विकल्प बचती है जिसका बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश में देखने को मिला।

इस आपदा के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव और उनके कार्यकर्ताओं ने ज़मीनी स्तर पर लोगों की न सिर्फ़ लगातार मदद की, बल्कि स्वास्थ्य-आपदा की इस घड़ी में समाजवादी कार्यकर्ताओं ने अपनी जान पर खेलकर लोगों को जिस तरह से ऑक्सीजन, दवायें, राशन, समाजवादी रसोई के माध्यम से भोजन,रहने के लिये समाजवादी बसेरा, अंतिम संस्कार की सामग्री वंचित जनमानस तक पहुंचाई उससे समाजवाद की असल सोच मूर्त रूप लेती हुई नज़र आयी।

भारत जैसे देश जहां लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या अभी भी अपनी मूल-भूत जरूरतों को पूरा करने में ही असफल रही है वहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव द्वारा सभी लिए मुफ्त वैक्सीन की मांग न सिर्फ समाजवादी मूल्यों की परिचायक है बल्कि बहुसंख्यक जनता की ही आवाज़ है।

जब देश की अन्य बड़ी पार्टयों के नेता घर से निकलने तक के लिए तैयार नहीं थे,जब सत्ताधारी भाजपा ने अपने ही कार्यकर्ताओं से दूरी बना ली तब समाजवादी पार्टी के लाखों कार्यकर्ता श्री अखिलेश यादव के आह्वान पर बिना किसी भेदभाव के जनता की सेवा में डट गये और लगातार जनता के दुःख दर्द में शामिल हो कर अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

जब आपदा बड़ी हो,संकट बड़ा हो, तब समाज के बीच,जनसामान्य के साथ कंधे से कंधा मिलाकर,लोगों के दुःख और परेशानी में खड़े रहने की ज़रूरत सबसे ज्यादा होती है,जिसमें सरकार तो पूर्णतया फेल हो गयी परन्तु कोविड19 आपदा की इस घड़ी में समाजवादी विचारधारा के लोगों ने जान की परवाह किये बग़ैर जनता के दुःख-दर्द के निराकरण में अग्रणी भूमिका निभायी। इतिहास गवाह है की समाजवादी मूल्यों के तहत ही इस तरह की विपदाओं से लड़ा जाता रहा है।

समाजवादी पार्टी इन्हीं सामाजिक मूल्यों से गुंथे सिद्धांतों को अपनी राजनैतिक विचारधारा का मूल मानती है। समाजवादी सरकारों ने जिस तरह से आम जनता के लिए स्वास्थ्य सुविधांए सुधारने, इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का, समाजवादी एम्बुलेंस,अस्पतालों के निर्माण का कार्य समाजवादी सरकार के रहते किया उसने कोविड 19 की आपदा से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। सरकारी अस्पतालों में 1 रुपया का पर्चा और ग्रामीण इलाकों में एंम्बुलेंस पहुचाने का जो सफल प्रयास समाजवादी सरकार ने जमीनी स्तर पर किया था उसने इस संकट की घड़ी में भी जनता को

राहत पहुचानें का कार्य किया।

दरअसल कोरोना काल में पूरे देश में सबसे ज़्यादा अव्यवस्था और संकट का सामना उत्तर प्रदेश की जनता को करना पड़ा। उत्तर प्रदेश की दक्षिणपंथी भाजपा सरकार ने स्वास्थ्य आपातकाल के दौर में जनता की समस्याओं से अपना पल्ला झाड़ते हुए लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया। कोविड 19 की दूसरी लहर में तो स्थिति यहाँ तक पहुंच गई की लोग दवा- ऑक्सीजन, एम्बुलेंस और अस्पताल के अभाव में सड़कों पर दम तोड़ने लगे। लोग,अपनों की चंद सांसों को सहेजने के लिए व्यवस्था के हाथों लुट गए। अपनों को अंतिम विदाई भी सम्मान से न देने की पीड़ा के साथ-साथ श्मशान घाटों पर लगी लाशों की कतारें और गंगा समेत अन्य नदियों के किनारों पर दफ़न-उतनाते शवों

कोविड19 आपदा की इस घड़ी में समाजवादी विचारधारा के लोगों ने जान की परवाह किये बग़ैर जनता के दुःख-दर्द के निराकरण में अग्रणी भूमिका निभायी।

की वेदना ऐसी कि मानवता भी शर्मसार हो जाये।

साथ ही अस्पताल-दवाओं- वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर जिस तरह की अव्यवस्था उत्तर प्रदेश में फैली वह अपने आप में सभ्य समाज के लिए शर्म की बात है। प्रदेश का सरकारी तंत्र अपने उत्तरदायित्वों और जिम्मेदारियों को निभाने में न सिर्फ पूरी तरह से असफल हो गया बल्कि प्रदेश की जनता को भोजन-राशन और मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी संकट खड़ा हो गया।

सरकार ने बिना किसी विश्लेषण एवम मूल्यांकन के जनता को केंद्र में न रखते हुए ऐसे कई निर्णय लिये जिसने लोगों की जान को ही संकट में डाल दिया, लेकिन फिर भी उदासीनता औऱ बेशर्मी के साथ पूंजीवाद को केंद्र में रखकर निर्णय लेने वाली भाजपा सरकार अपनी जवाबदेही के बजाय "आपदा को अवसर" बनाकर अपने प्रचार-प्रसार में ही लगी रही जो कि भाजपा सरकार के जनविरोधी चरित्र का जीता-जागता प्रमाण है।

सच्चाई यह है कि वर्तमान कोविड 19 महामारी के प्रबंधन ने भारत समेत दुनिया की दक्षिणपंथी सरकारों के असली चेहरे को बेनक़ाब कर दिया है।

दक्षिणपंथी सरकारें अधिकाधिक लाभ के सिद्धांत पर कार्य करती है, इनका समाज और जनहित से कोई सरोकार नहीं होता है। आपदा में भी लाभं कमाने की प्रवृति बेहद घातक व दक्षिणपंथी विचारधारा का प्रमुख चरित्र है। भारत में कोविड 19 महामारी के प्रबंधन के दौरान दक्षिणपंथी भाजपा सरकार ने जनसरोकारों को दरकिनार करते हुए कालाबाज़ारी और जमाख़ोरी की अनदेखी से भी गुरेज़ नहीं किया।

प्रखर समाजवादी औऱ समग्र चिंतक डॉ राममनोहर लोहिया कहा करते थे कि पूंजीवाद (दक्षिणपंथ) की दो संताने हैं, पहला गरीबी और दूसरा युद्ध।

नब्बे के दशक में पूंजीवाद ने तीसरी संतान को जन्म दे दिया और वह है 'आपदा पूंजी' (डिज़ास्टर कैपिटल) - पहले आपदा पैदा करना और फिर उस आपदा को अवसर मानकर उसका अमानवीय ढंग से पूंजीकरण करना (The Shock Doctrine by Naomi Klein)

वहीं, समाज की संवृद्धि, विकास एवं समरसता के लिये समाजवादी विचारधारा मुख्य रूप से तीन महत्वपूर्ण पहलुओं पर सर्वाधिक ज़ोर देती है। पहला - समाज केंद्रित नीतियां, जनकल्याणकारी राज्य और जनकेंद्रित राजनीति। दूसरा, सामाजिक समरसता, समाज सेवा और जनता के प्रति किसी भी परिस्थिति और आपदा में समर्पण का भाव और प्रतिबद्धता। तीसरा वैज्ञानिक सोच और वैज्ञानिक नीतियां।

समाजवादी विचारधारा इस विचार पर ज़ोर देती है कि स्वास्थ्य, रोज़गार, शिक्षा एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की पहली जिम्मेदारी सरकार और राज्य की होती है। समाजवादी सरकारों का ज़ोर हमेशा जनस्वास्थ्य और जन कल्याणकारी योजनाओं पर होता है। समाजवादी विचार आपदा और संकट की मुश्किल की घड़ी में गरीब- मजदूर और परेशान जनता को बाजार यानी पूंजीवाद के भरोसे नहीं छोड़ता बल्कि सरकार द्वारा ज़िम्मेदारी निभाये जाने की वकालत करता है। समाजवाद के विपरीत पूंजीवाद का जोर हमेशा पूंजीपतियों, निजीकरण, मुनाफा, मुक्त बाजार और निजी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर होता है, पूंजीवादी सरकारें समाज और जनता के मुकाबले पूंजी और पूंजीवादियों को अपने केंद्र में रखती हैं।

कोविड19 वैश्विक आपदा में दुनिया भर में

समाजवादी रसोई

Shot on vivo S1
AI Triple Camera

पीड़ितों की मदद लगातार जारी रखें

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों एवं पूर्व तथा वर्तमान सांसद पूर्व एवं वर्तमान विधायकों को निर्देश दिया है कि वे आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कोरोना पीड़ितों की मदद करने का काम लगातार जारी रखे।

उन्होंने कहा कि गांवों में रहकर जरूरतमंदों को राहत पहुंचाएं। लगातार जनसंपर्क करते हुए वे देखे कि कोई आस पड़ोस में भूखा न सोए इसके लिए समाजवादी रसोई चला सकते हैं। अपने को सुरक्षित रखते हुए कोरोना संक्रमण या अन्य बीमारी से मृत व्यक्ति के आश्रितों को संकट की इस घड़ी में सांत्वना दें।

श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार के गलत प्रबंधन के चलते कोरोना महामारी ने लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। अभी भी इसका प्रकोप थमा नहीं है। गांवों में स्थिति बहुत गंभीर है। वहां दवा, इलाज की सुचारू व्यवस्था नहीं है। टीकाकरण जिस सुस्त रफ्तार से चल रहा है दिवाली तक उसका लक्ष्य पूरा होना संभव नहीं।

श्री यादव ने कहा कि संकट की इस घड़ी में हमें जनसामान्य के सुख दुःख में सक्रिय भागीदारी निभानी है। किसी भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी को तब तक चैन से नहीं बैठना है जब तक प्रदेश से भाजपा की जनविरोधी सरकार को हटाकर समाजवादी सरकार न बन जाये।

यह देखने को मिला कि जहां-जहां सरकारें समाजवादी विचारधारा और सोच की हैं, वहाँ कोरोना आपदा से लड़ने में सरकारों को ज्यादा सफलता मिली है और जनसामान्य को अपेक्षाकृत कम मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। उदहारण के तौर पर जर्मनी, पुर्तगाल और आइसलैंड जैसे देश हैं। इन देशों में समाजवादी सरकारों ने आपदा से पहले और आपदा के समय जनता को केंद्र में रखते हुए नीतियां और योजनाएँ बनायीं और जनस्वास्थ्य सेवाओं पर भरपूर जोर दिया। परिणाम स्वरुप कोविड1 9 से संक्रमित होने वालों कि न सिर्फ़ संख्या कम रही बल्कि मृत्य दर भी कम रही । इन सभी देशों को कोरोना पर जल्द नियंत्रण में भी बड़ी सफलता मिली।

महत्वपूर्ण बात ये भी है कि कोविड19 आपदा ने पूंजीवादी देशों को भी समाजवादी नीतियों को लागू करने पर मजबूर कर दिया. यहाँ तक कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पूंजीवादी देश को भी आपदा के समय निजी स्वास्थ्य व्यवस्था के बजाय जनस्वास्थ्य व्यवस्था और जनकल्याणकारी व्यवस्था पर निर्भर होना पड़ा ।

समाजवादी विचारधारा का महत्वपूर्ण पहलू है वैज्ञानिक सोच, जिसका अर्थ होता समस्या का वैज्ञानिक आकलन, विशेषज्ञों से सलाह व निराकरण के वैज्ञानिक उपाय जबकि वर्तमान सरकार ने कोविड 19 से लड़ने में वैज्ञानिक सोच की जगह शंख-घंटा-घड़ियाल और मोमबत्ती जलवाकर, निराकरण के स्थान पर समस्या से ध्यान भटकाया।

(लेखिका इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय छात्रसंघ की पूर्व अध्यक्ष हैं)

फोटो फीचर

साथ खड़े हैं समाजवादी

समाजवादी
राशन
समाजवादी
रसोई द्वारा

BITS
समाजवादी पार्टी

श्री साईंधाम धर्मार्थ
होम्योपैथिक औषधालय
निःशुल्क सेवा
मन्दिर परिसर के सामने
वाहन खड़ा न करें।
NO PARKING
बाइस में
बाइसिकल
पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की प्रेरणा से
रसोई द्वारा भोजन वितरण
जनपद मुजफ्फरनगर
निवेदक

समाजवादी रसोई

बातें कम, काम ज्यादा
सबका काम, सबका सम्मान
हम हैं पश्चिम के अरमान

इलाहाबाद बैंक
ए.टी.एम.

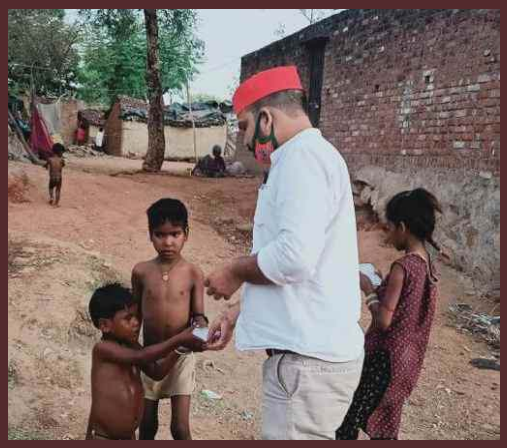

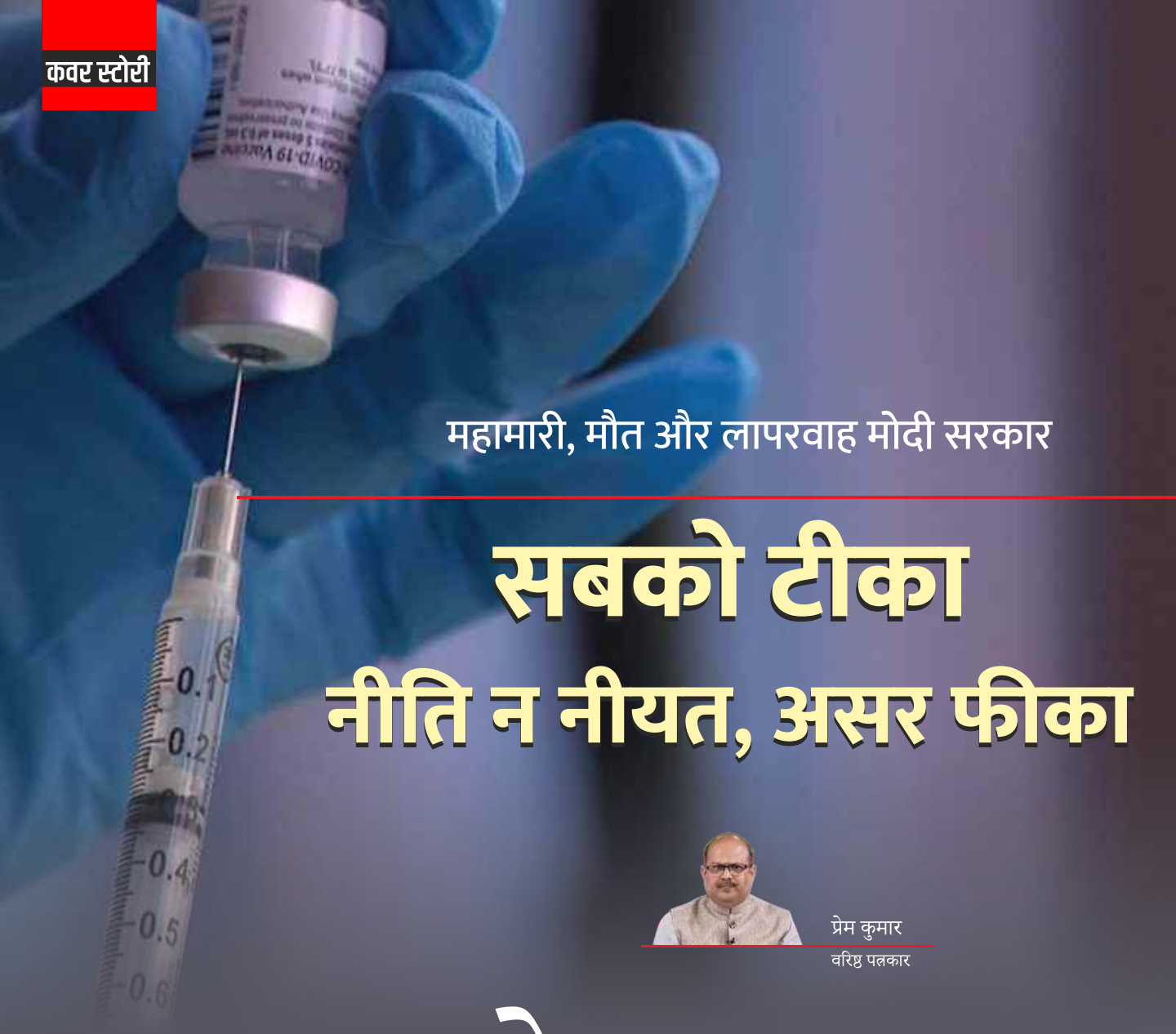

महामारी, मौत और लापरवाह मोदी सरकार

सबको टीका
नीति न नीयत, असर फीका

प्रेम कुमार
वरिष्ठ पत्रकार

कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव से निपटने के लिए जब एक ओर दुनिया के कई देशों ने अपने नागरिकों को सुरक्षित रखने को प्राथमिकता दी वहीं भारत में नरेन्द्र मोदी की सरकार ने हमेशा की तरह इसे भी एक इवेंट में तब्दील करने पर ही पूरा ध्यान लगाया। जिसके केन्द्र में था अपनी वाहवाही करता स्व प्रचार। नतीजा यह कि टीकाकरण यानी वैक्सीन को लेकर न कोई ठोस नीति बनी न सरकार की नीयत ही झलकी। जब हालात बिगड़े तो अफरातफरी मची है।

अंतत: तय हुआ है कि अब राज्य सरकारों को अब वैक्सीन खरीदने की जरूरत नहीं होगी। केंद्र सरकार खुद वैक्सीन की खरीद करेगी। 21 जून योग दिवस की तारीख से देशभर में 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन दी जा रही है। वास्तव में 21 जून से शुरू टीकाकरण का यह अभियान ही देश की जरूरत थी जिसे लागू करने में 5 महीने 5 दिन की देरी हुई है। इस देरी का खामियाजा पूरे देश ने भुगता है।

5 महीने 5 दिन की देरी का अंजाम		
तारीख	कोरोना संक्रमण	कोरोना से मौत
16 जनवरी'21	1.58 करोड़	1.52 लाख
13 जून' 21	2.58 करोड़	3.74 लाख

16 जनवरी को भारत में 1.58 करोड़ लोगों में कोरोना का संक्रमण बढ़ते हुए 13 जून को 2.58 करोड़ जा पहुंचा। यानी लगभग दोगुना। 16 जनवरी को मौतों का जो आंकड़ा 1.52 लाख था वह 13 जून को 3.74 लाख पार कर गया। ढाई गुणा ज्यादा मौत हुई। मौत के सही आंकड़े तो दर्ज ही नहीं हुए। वे नदियों में उतरातीं लाशें बनकर या नदी किनारे दफन होकर रह गयीं।

सुलगते सवाल

आखिर क्यों मोदी सरकार देश की आवश्यकता के हिसाब से वैक्सीन की नीति नहीं अपना सकी?

क्यों गलत वैक्सीन नीति का खामियाजा देश को भुगतना पड़ा?

क्या देश में कोरोना की दूरी लहर और इस दौरान हुई बेहिसाब मौत के पीछे ठोस वैक्सीन नीति का अभाव बड़ी वजह नहीं है?

गलत वैक्सीन नीति के खिलाफ देश में बेचैनी, राज्य सरकारों की ओर से उठ रही आवाज़ और जनहित में सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने की वजह से वैक्सीन नीति को लेकर सरकार सजग हुई और उसे अपनी गलती सुधारनी पड़ी। वैक्सीन नीति में गलतियां सुधारते हुए भी केंद्र सरकार ने अपनी गलती मानी नहीं। बल्कि इसका ठीकरा राज्य सरकारों पर फोड़ डाला।

लगातार यू टर्न के बीच सवालों में वैक्सीन नीति

राष्ट्र के नाम संबोधन में 7 जून को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने घोषणा की कि अब राज्य सरकारों को वैक्सीन खरीदने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार उत्पादक से वैक्सीन खरीदेगी और फिर राज्य सरकारों को मुहैया कराएगी। हालांकि बाद में स्पष्ट किया गया कि वैक्सीन उत्पादन का 75 फीसदी ही केंद्र सरकार खरीदेगी। 25 फीसदी वैक्सीन निजी अस्पतालों के लिए सुरक्षित रहेगी। पीएम मोदी ने बताया कि राज्य सरकारों को वैक्सीन वितरण की जिम्मेदारी उनके आग्रहों को देखते हुए दी गयी थी जिसे ज़रूरत के हिसाब से अब बदला जा रहा है। जबकि, सच यह है कि सिर्फ महाराष्ट्र और प.बंगाल की सरकारों ने इस बाबत चिट्ठियां लिखी थीं और उसके भी संदर्भ और मायने अलग थे।

केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति में डेढ़ महीने के भीतर यह बड़ा बदलाव आया। तय हुआ है कि 21 जून को योग दिवस की तारीख से देश में 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन देने का अभियान शुरू होगा। यही वह अभियान है जिसकी अपेक्षा यह देश वैक्सीन हासिल होने के बाद से कर रहा था। 16 जनवरी को शुरू हुए टीकाकरण अभियान में इतनी बार बदलाव हुआ कि सरकार की वैक्सीन नीति ही सवालों के घेरे में आ गयी।

पीएम मोदी ने दुनिया में कटायी भारत की नाक

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने बड़बोलेपन की वजह से पूरी दुनिया में भारत की नाक कटा दी। कोरोना को हराने, मानवता को बचाने का दंभ भरा और दुनिया को मदद का एलान कर डाला। लेकिन, कोरोना की दूसरी लहर में स्थिति ऐसी बनी कि भारत खुद दुनिया के देशों से मदद लेता दिखा।

भारत में नये साल 2021 की शुरुआत कोविशील्ड और कोवैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिलने के साथ हुई थी और टीकाकरण का अभियान 16 जनवरी को शुरू हो गया। इंग्लैंड में 8 दिसंबर 2020 को यह अभियान शुरू हो चुका था। इस हिसाब से हम पीछे थे मगर, हमारे हमारे पास स्वदेशी वैक्सीन के साथ दो-दो वैक्सीन थे और ऐसा लग रहा था कि कोरोना से लड़ाई में भारत दुनिया को राह दिखलाएगा। 30 जनवरी तक 37.4 लाख कोरोना वैरियर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दिए जा चुके थे।

कोरोनो को हराने के दंभ की खुली पोल

28 जनवरी को दावोस में वर्ल्ड इकॉनोमिक फोरम में भारतीय प्रधानमंत्री ने कोरोना से जंग में भारत की जीत का एलान किया। भारत में कोरोना से लड़ने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी कहा कि कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण कर भारत ने पूरी मानवता को बड़ी त्रासदी से बचाया है। मोदी ने भारत को ऐसे देश के रूप में पेश किया जिसने पूरी दुनिया

में सबसे ज्यादा नागरिकों की जान बचाने का काम किया। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सिनेशन कार्यक्रम की घोषणा करते हुए पीएम मोदी ने दुनिया की मदद करने का भी एलान किया।

बढ़ती मौतों के बीच निर्यात की गयी वैक्सीन!

पीएम मोदी की दुनिया को वैक्सिनेशन में मदद के एलान के बाद से भारत में कोरोना संक्रमण और इससे होने वाली मौत लगातार बढ़ती चली गयी। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि फरवरी 2021 के महीने में 2882 लोगों की मौत हुई। मार्च में आंकड़ा दोगुना से ज्यादा हो गया और यह 5766 तक जा पहुंचा। अप्रैल में यह साढ़े 8 गुणा बढ़कर 48,879 हो गया। मई महीने में मौत का आंकड़ा 1,20,072 जा पहुंचा। जबकि जून के पहले पखवाड़े में तकरीबन 40 हजार लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी थी।

21 अप्रैल तक सीरम इंस्टीच्यूट ऑफ इंडिया 6 करोड़ 62 लाख वैक्सीन के डोज 95 देशों को निर्यात कर चुका था। इनमें 1.98 करोड़ कोवैक्स कार्यक्रम के लिए, 1.07 करोड़ गरीब देशों के लिए अनुदान के तौर पर और 3.57 करोड़ की खुले बाजार में बिक्री हुई।

वैक्सीन नीति पर यू टर्न : जब रोकना पड़ा वैक्सीन का निर्यात

वैक्सीन निर्यात पर रोक लगा दी गयी। इसकी आधिकारिक घोषणा कभी नहीं हुई। मगर कोविशील्ड की निर्माता कंपनी के अदार पूनावाला ने 7 अप्रैल को एसोसिएट प्रेस को दिए इंटरव्यू में वैक्सीन निर्यात पर प्रतिबंध की पुष्टि की और उम्मीद जताई कि अगले दो महीने में वैक्सीन निर्यात दोबारा शुरू हो सकेगा। कोवैक्स अभियान की ओर से भी वैक्सीन की आपूर्ति में सीरम इंस्टीच्यूट की ओर से देरी की बात कही गयी थी।

वैक्सीन नीति पर यू टर्न की अहम तारीखें

16 जनवरी 2021 : हेल्थकेयर वर्कर्स के साथ वैक्सिनेशन की शुरुआत

1 मार्च 2021 : सीनियर सिटिजन और

वैक्सीन पर भाजपा ने जनता को धोखे में रखा

बुलेटिन ब्यूरो

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार ने कोरोना संक्रमण से बचाव पर कम अपने राजनीतिक स्वार्थ साधन पर ज्यादा ध्यान दिया है। विशेषज्ञों की राय पर चलने के बजाय भाजपा बर्बादियों का उत्सव मनाती रही। उसने हमेशा जनता को धोखे में रखा है। वैक्सीन को लेकर भाजपा सरकार ने जैसी अनिर्णय भरी लापरवाही प्रदर्शित की है उससे कोरोना संक्रमण का संकट ज्यादा बढ़ गया। बार-बार पैंतरा बदले जाने से जनता के मन में अविश्वास भी पैदा हुआ।

यह बात तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री अमर्त्य सेन ने भी कही है कि "भारत सरकार ने भ्रम में रहते हुए कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए काम करने के बजाय अपने कामों का श्रेय लेने पर ध्यान केंद्रित किया। भाजपा नेतृत्व काम कम वाहवाही ज्यादा लेने पर भरोसा करती है। लेकिन जनता भाजपा राज के कारनामों से भलीभांति परिचित हो चुकी है और वह अब उसकी चालों में आने वाली नहीं है।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने कोरोना संकट काल में भी अपनी फरेबी राजनीति से परहेज नहीं किया। समाजवादी पार्टी के प्रति उसका कुप्रचार अभियान चलता ही रहता है। जन दबाव में आखिरकार भाजपा सरकार ने सभी को टीका लगवाने का ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी का यही मानना रहा है कि गरीबों तथा अन्य सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगनी चाहिए। भाजपा उल्टे वैक्सीन के मामले में कई रंग बदल चुकी है। उसके कारण ही जनता में वैक्सीन के प्रति उदासीनता दिखाई दी। यह भाजपा के प्रति जनता के अविश्वास की भी द्योतक है।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि जिस धीमी रफ्तार से वैक्सीन का

दूसरी बीमारियों वाले 45+ आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सिनेशन

1 अप्रैल 2021 : 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन की शुरुआत

1 मई 2021 : 18+ और -45 आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सिनेशन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में 16 जनवरी को पहले चरण में टीकाकरण अभियान की चर्चा की थी और कहा था कि 3 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोविड का टीका लगाया जाएगा। इसका खर्च केंद्र् सरकार उठाएगी। अगले कुछ महीने में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने की बात भी उन्होंने की थी। इस अनुसार 1 मार्च से सीनियर सिटिजन और दूसरी बीमारियों वाले 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सिनेशन शुरू किया गया।

एक लक्ष्य पूरा नहीं, दूसरा अभियान शुरू

अभी प्राथमिकता वाले 30 करोड़ में से महज 6.51 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन लग पायी थी कि 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया। मार्च महीने में 11 लाख 8 हजार से ज्यादा कोरोना के नये संक्रमण मिल चुके थे। संभवत: इस दबाव में वैक्सिनेशन पर यह नयी नीति आयी और बड़ा यू टर्न लिया गया। तर्क यह दिया गया कि कोविड से मरने वालों में 45 साल से अधिक उम्र के लोग अधिक हैं इसलिए उन्हें वैक्सिनेट किया जाना जरूरी है। मगर, यही तर्क अब तक गायब क्यों रहे इसका जवाब देने की जरूरत सरकार ने नहीं समझी।

संक्रमण, मौत, महाकुंभ और चुनाव के बीच असफल 'टीका उत्सव'

अप्रैल का महीना कोरोना संक्रमण के नजरिए से बहुत तनाव के साथ शुरू हुआ। 4 अप्रैल को 1 लाख से ज्यादा संक्रमण मिले। पहली लहर के चरम का रिकॉर्ड टूट गया और फिर आगे 6 जून तक कभी 1 लाख से

नीचे कोरोना संक्रमण का आंकड़ा नहीं आ सका। इस दौरान ऑक्सीजन की कमी से हो

कार्यक्रम चल रहा है उससे यह स्पष्ट है कि भाजपा तो सभी का टीकाकरण का लक्ष्य दिवाली तक पूरा करने से रही। टीकाकरण कार्यक्रम तो अब बस सन 2022 में समाजवादी सरकार बनने पर ही गति पकड़ सकेगा। सबको मुफ्त वैक्सीन देने का वादा समाजवादी सरकार में ही पूरा होगा। जो लोग टीका नहीं लगवा सके उनसे भी टीका लगवाने की अपील की गई है।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने बड़े जोर शोर से प्रचारित किया था कि वह कोरोना के निजी इलाज का खर्च देगी। अब भाजपा बताए कि अभी तक जनता के कितने बिलों का भुगतान किया गया है। जनता के सामने सरकार अपना आंकड़ा रखे।

सरकारी विज्ञापनों के बोझ तले दबकर भाजपा सरकार की बदइंतजामी से ऑक्सीजन, बेड और अब टीके के लिए जूझ रही जनता के सवालों का जवाब नहीं देने वाले भाजपाई प्रोपैगंडा रचने वालों को जनता माफ नहीं करेगी।

रही मौतों और अदालत की टिप्पणियों ने केंद्र में मोदी सरकार की फजीहत कर डाली। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री की रैलियों से भी जनता में आक्रोश पनपा। इस दौरान हरिद्वार महाकुंभ में लाखों लोगों का गंगा स्नान जारी था। जब साधु-संतों के भी कोरोना पीड़ित होने की खबरें आने लगीं तो आखिरकार 17 अप्रैल को महाकुम्भ को प्रतीकात्मक बनाने की अपील प्रधानमंत्री को करनी पड़ी।

इससे पहले 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाते हुए भीम राव अंबेडकर की जयंती मनायी गयी। पश्चिम बंगाल में चुनाव को देखते हुए भी इसका महत्व था। मगर, वैक्सीन की कमी के कारण यह टीका उत्सव असफल रहा। चार दिन में कुल 1 करोड़ 28 लाख 98 हजार 91 लोगों को टीके पड़े। इससे पहले 8,9 और 10 अप्रैल को सिर्फ तीन दिन में 1 करोड़ 13 लाख 96 हजार 474 लोगों को टीके लगाए गये थे। सच यह है कि केरल, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में वैक्सीन की कमी की शिकायत कोरोना उत्सव के दौरान ही आने लग गयी थी।

वैक्सीन की कमी के बीच 18+ वर्ग को वैक्सीन का ऐलान

19 अप्रैल को केंद्र सरकार ने अपनी छवि सुधारने के लिए या फिर आलोचनाओं से बचने के लिए बड़ा फैसला किया। देश के अग्रणी डॉक्टरों और फार्मा कंपनियों के साथ बैठक के बाद यह फैसला लिया गया कि 1 मई से सभी वयस्कों को वैक्सीन दी जाएगी। यह फैसला तब लिया गया जब राज्य वैक्सीन की कमी की शिकायत कर रहे थे और वैक्सीन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया था।

न सिर्फ सभी वयस्कों के लिए वैक्सीन की शुरुआत कर दी गयी, बल्कि वैक्सीन की खरीद की जिम्मेदारी समेत कई नीतियों में बड़ा बदलाव हुआ जिस पर गौर करें-

1 मई को बदली वैक्सीन पॉलिसी की अहम बातें

18 की उम्र से अधिक और 44 वर्ष तक की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन की खरीद का जिम्मा राज्य सरकारों पर डाल दिया गया।

50 फीसदी वैक्सीन की खरीद का जिम्मा खुद केंद्र सरकार ने अपने पास रखा।

वैक्सीन की अलग-अलग कीमत तय कर दी गयी।

- वैक्सीन अब केंद्र सरकार के लिए सस्ती और राज्य सरकारों के लिए महंगी हो गयी। निजी अस्पतालों के लिए सबसे महंगी।

केंद्र ने 50 फीसदी वैक्सीन की खरीद अपने पास सुनिश्चित कर राज्यों के लिए वैक्सीन की उपलब्धता को मुश्किल बना दिया। उत्पादक किसे वैक्सीन पहले दे, यह उसकी मर्जी पर था। झारखण्ड जैसे राज्य ने

खुलकर कहा कि सीरम इंस्टीच्यूट ने 1 मई से पहले वैक्सीन देने से मना कर दिया है। जब वैक्सीन मिलेगी तभी 18 से अधिक उम्र वाले वर्ग में वैक्सिनेशन की शुरुआत होगी।

1 मई को सिर्फ 9 राज्य ही टीकाकरण अभियान शुरू कर सके। इन राज्यों में भी उम्मीद से कम वैक्सिनेशन हुए। दिल्ली में 40 हजार, महाराष्ट्र में 73 हजार, राजस्थान में 76 हजार और गुजरात में 1.08 लाख वैक्सीन के डोज दिए जा सके। देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में, जहां भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार है, महज 7 जिलों में 1 मई को टीकाकरण का अभियान शुरू किया जा सका। यह प्रतीकात्मक अभियान बनकर रह गया।

पीआईबी की ओर से 14 जून को जारी वक्तव्य में कहा गया है कि 18-44 साल के आयुवर्ग में अब तक 4.37 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। पूरे देश में 14 जून तक 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी चुकी थी।

वैक्सीन नीति पर बडा सवाल : वैक्सीन को मंजूरी दी, ऑर्डर नहीं दिए

वैक्सीन पॉलिसी की यह सबसे बड़ी खामी थी कि कोविशील्ड को मंजूरी देने से पहले तक कोई एडवांस ऑर्डर नहीं दिया गया। पहला ऑर्डर मात्र 1.5 करोड़ वैक्सीन का था। यह चौंकाने वाली बात है। जिस देश में 18 साल से अधिक आयु के 90 से 95 करोड़ लोग हों और दो डोज के हिसाब से 2 अरब वैक्सीन की जरूरत हो, उस देश में वैक्सीन के ऑर्डर की कोई योजना ही ना रही हो, तो यह वैक्सीन पॉलिसी पर बहुत बड़ा सवाल है।

जब चरम पर था कोरोना, घट गया वैक्सिनेशन

माह	वैक्सिनेशन
अप्रैल	8.7 करोड़
मई	6.9 करोड़
जून	4.26 करोड़ (14 जून तक)

अप्रैल महीने में 8.7 करोड़ वैक्सीन दिए गये, मई महीने में 6.9 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिए गये। जून में 14 तारीख तक 4.26 करोड़ वैक्सीन दिए जा चुके हैं। वैक्सीन लेने वालों के ये घटते आंकड़े हैं जो देश की वैक्सीन पॉलिसी पर बड़ा सवाल उठाते हैं। एक तरफ अलग-अलग वर्गों में वैक्सीन को अभियान के तौर पर शुरू किया गया, दूसरी तरफ वैक्सीन की उपलब्धता नहीं बढ़ाई गयी। बल्कि, यह घटती चली गयी।

अदालत में कुछ और बोल रही थी केंद्र सरकार

यह बात खास तौर से उल्लेखनीय है कि 1 मई से 18+ के वैक्सीनेशन के लिए बनी नयी पॉलिसी में कहा गया था कि उत्पादक से उत्पाद का आधा हिस्सा केंद्र खरीदेगा, बाकी राज्य सरकारें। लेकिन, अदालत में दिए गये केंद्र के हलफनामे में नयी बात यह सामने आयी कि बाकी 50 फीसदी में 25 फीसदी ही राज्य सरकारें खरीद सकेंगी। शेष 25 फीसदी निजी अस्पताल खरीदेंगे। यह हलफनामा भी केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति में नया यू टर्न था।

जब राज्य सरकारें लगातार वैक्सीन की कमी की शिकायत करने लगे, वैक्सीन सेंटरों पर नो वैक्सीन के बोर्ड टांगे जाने लगे, लोग वैक्सीन सेंटर से लौटने लगे और मीडिया में खबरें आम हो गयीं तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: इसका संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से वैक्सिनेशन पॉलिसी की समीक्षा करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन की अलग-अलग कीमतों से लेकर एक साथ वैक्सीन की खरीद नहीं होने, बजट में 35 हजार करोड़ रुपये होने के बावजूद खर्च नहीं करने जैसे मुद्दों पर अहम सवाल भी पूछे। जब केंद्र सरकार के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया तो एक बार फिर वैक्सीन नीति में निर्णायक यू टर्न लेकर मोदी सरकार उपस्थित हो गयी।

केंद्र सरकार ने लगातार वैक्सीन पॉलिसी में बदलाव किए। आलोचनाओं का सामना किया। कई बार कोविड-19 से हो रही मौतों के समक्ष सरकार लाचार दिखी। कोविड से लड़ने की सारी तैयारी के दावे धरे रह गये। अस्पतालों की दुर्दशा सामने आयी। ऑक्सीजन का प्रबंधन नहीं हो पाने के कारण लगातार मौतें हुईं। इस बीच हर महीने वैक्सीन नीति में बदलाव होते रहे। जबकि, कोरोना से लड़ाई के तौर पर अबतक वैक्सीन को ही एकमात्र उपाय के तौर पर सरकार पेश करती रही। अगर वैक्सीन ही इकलौता बचाव है तो सरकार ने एक समान वैक्सीन नीति अपनाने में देरी क्यों की? इसका जवाब आने वाले समय में हमेशा मोदी सरकार से पूछा जाता रहेगा।

राजकाज गोल कुर्सी डांवाडोल

बुलेटिन ब्यूरो

कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में सरकार कैसी चल रही है इसकी बानगी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की हालिया घटनाओं से मिलती है। तब जबकि कोरोना की दूसरी लहर से उपजी त्रासदी के जख्म ताजा हैं और तीसरी लहर की आशंका से आम लोग भयभीत हैं तब भाजपा नेतृत्व की आंतरिक खींचतान का राज्य के काम पर भी प्रभाव पड़ रहा है। जनहित के निर्णयो में देरी के साथ तमाम विकास योजनाएं भी ठप्प हैं। सरकारी मशीनरी कुंठित और निष्क्रिय भूमिका में है। इलाज, दवा सभी की मारामारी से चारों तरफ हाहाकार मचा है।

रोजाना बिगड़ती स्थितियों में सत्ता पाने के चार वर्ष बाद भाजपा और सरकार में तालमेल बिठाने के लिए संगठन नेतृत्व को बैठक करनी पड़ रही है। इन बैठकों और संघ के परामर्श का एकमात्र उद्देश्य फिर सत्ता पर काबिज होना है। राज्य कोरोना के संकट से अभी उभरा भी नहीं कि भाजपा सत्ता के लिए बदहवास है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए झूठी कहानियां गढ़ी जाने का दौर चल रहा हैं।

दरअसल उत्तर प्रदेश कोरोना संक्रमण के साथ राजनीतिक संक्रमण से भी जूझ रहा है। भाजपा सरकार के कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में अब मुख्यमंत्री का नियंत्रण भी ढीला पड़ता जा रहा है। जिस तरह से दिल्ली-लखनऊ के बीच तनातनी के संकेत हैं उससे लगता है कि जो दिख रहा है वह अगले संकट का संकेत है। सरकार नाकाम है और मुख्यमंत्री जी निष्क्रिय फिर भी दिल्ली की दौड़ किस लिए हो रही है राज्य की जनता सच्चाई से परिचित है। मुख्यमंत्री को प्रदेश की जनता को बिगड़ते हालात की जवाबदेही देनी पड़ेगी

इसमें भी दो राय नहीं कि भाजपा ने राजनीतिक संक्रमण फैलाने में कम योगदान नहीं किया है। शासन प्रशासन को साम्प्रदायिक आधार पर चलाने का कुप्रयास भाजपा सरकार ने किया है। इस सरकार ने बदले की भावना से विपक्षी नेताओं के खिलाफ निंदा अभियान चलाकर अपनी घटिया मानसिकता प्रदर्शित की है। भाजपा राज में कोरोना एक्ट की सारी कार्यवाही विपक्ष और आम जनता के लिए है। कोरोना प्रोटोकाल तोड़ने वाले भाजपा नेताओं के सामने प्रशासन अंधा बना रहा।

बंदरबांट में उलझी भाजपा सरकार से जनता को कोई उम्मीद नहीं बची है। भाजपा राज में बेकारी-बेरोजगारी रिकार्ड तोड़ रही है। मंहगाई थमने का नाम नहीं ले रही है। पेट्रोल-डीजल-रसोई गैस सबके दाम आसमान छू रहे है। न मनरेगा में काम है, न स्किल मैपिंग का कहीं अता-पता है। व्यापार, कारोबार, दुकानदारी सब ठप्प है। लघु-मध्यम उद्योग बर्बाद हो रहे हैं।

वस्तुतः संघी-भाजपाई छद्म राष्ट्रवाद की खोखली नैतिकता की आड़ में जनता और देश-प्रदेश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उनका संकल्प पत्र झूठ का पुलिंदा साबित हुआ है। वादाखिलाफी का उनका रिकॉर्ड जनता के सामने है। जनता ही उनको वादा स्मरण करायेगी। और वादा न निभाने

भाजपा सरकार के बस कुछ ही दिन शेष

बुलेटिन ब्यूरो

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा की डबल इंजन सरकार यार्ड में खड़े-खड़े जंग खाने से स्टार्ट होने की दशा में नहीं रह गयी है। इसलिए उसे रेलवे की सिकलाइन में पहुंचा दिया गया है। दिल्ली से आए पर्यवेक्षकों ने भी मान लिया है कि जब इस सरकार को जाना ही है तो ज्यादा माथापच्ची क्यों की जाए? ध्यान भटकाने के लिए नए-नए प्रोपैगंडा और हंथकडे ही भाजपा का शासन है।

श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि चिंतन-मनन, मंथन और भोजन-विश्राम के बीच ही भाजपा अपनी चुनावी रणनीति बनाती है। उत्तर प्रदेश में चुनाव सिर पर है और कोरोना से ज्यादा भाजपा सरकार के कुशासन से जनता त्रस्त है। कोरोना और फंगस संक्रमण के इलाज में लापरवाही के चलते लाखों जाने गई हैं। गांवो में स्थिति तो और ज्यादा खराब है। वहां दवा, इलाज की अव्यवस्था है। कानून व्यवस्था चौपट है। अब भाजपा नेतृत्व को लगने लगा है कि उसके राज में सरकार के बस कुछ ही दिन शेष बचे हैं सत्ता हाथ से जा रही है, इसलिए हड़बड़ाहट में भाजपा नेतृत्व दिल्ली से लखनऊ तक दौड़ लगाने लगा है।

उन्होंने कहा कि सच तो यह है कि भाजपा का कार्यकर्ता और आरएसएस स्वयंसेवक दोनो अपनी उपेक्षा के चलते विश्राम की मुद्रा में चले गए है। नेतृत्व उनके विद्रोही तेवरों से हैरान है। जनता में समाजवादी पार्टी की पैठ से डरा सहमा भाजपा का शीर्ष नेतृत्व दिल्ली से लखनऊ तक एसी कमरो में चिंतन-मनन, मंथन और भोजन के साथ लगातार बैठकों में लग गया है। लेकिन हालात ये है कि इसके भेजे गए दूत एक को मनाते हैं तो दूसरा रूठ जाता है। सरकार और संगठन में दरार-रार पाटने के लिए ट्वीट पर ट्वीट कर किसी तरह अपना पिंड छुड़ाकर नेतागण विश्राम मुद्रा में चले जा रहे है।

वहीं सरकार झूठे आंकड़ों के सहारे जनता को बरगलाना चाहती है। कोरोना संक्रमित कर्मचारियों के ड्यूटी पर मौत के मामलो को छुपाकर मुआवजा देने से बचना चाहती है। अपनी नाकामी छुपाने को कोरोना से मृतक संख्या को कम बता रही है, लेकिन जनता को बरगलाने में भाजपा अब सफल नहीं होगी। जनता ने निश्चय कर लिया है कि 2022 में भाजपा की विदाई और समाजवादी सरकार बनना तय है। भाजपा बढ़ते जनाक्रोश और किसान आंदोलन से डरी हुई है। इसी से उत्तर प्रदेश में कभी संगठन में तो कभी सरकार में फेरबदल की चर्चा छेड़ी जाती है। लेकिन अब लोग गुमराह होने वाले वाले नहीं है।

का दंड भी देगी। राज्य की पीड़ित जनता के साथ 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर न्याय हो सकेगा। उत्तर प्रदेश में जनता ने भाजपा को हटाने का मन बना लिया है। जनता को लुभावने जुमलों और झूठ की आड़ में भाजपा सरकार ने चार साल काट लिए अब उसके जाने के दिन ही गिने जा रहे हैं।

डांवाडोल होती कुर्सी को बचाने की आपाधापी के बीच भाजपा सरकार दावा कर रही है कि दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर का पुख्ता इंतजाम सरकार ने कर लिया है जबकि दूसरी लहर के इंतजाम ही पूरे नहीं हो पाए हैं। ब्लैक फंगस के इलाज में तो अक्षम्य लापरवाही हो रही है। सरकार आवश्यक इंजेक्शन तक नहीं उपलब्ध करा पा रही है। मरीज तड़प-तड़प कर जान दे रहे हैं। लखनऊ के अस्पतालों में जिलों से भी ब्लैक फंगस के मरीज आ रहे हैं। इनके समुचित इलाज की कही व्यवस्था नहीं है। सरकार इनके लिए जीवन रक्षक इंजेक्शन भी नहीं मुहैया कर पा रही है।

सपा के प्रति बढ़ता जा रहा रूझान

बुलेटिन ब्यूरो

जैसे-जैसे विधानसभा के चुनाव करीब आते जा रहे हैं वैसे-वैसे लोगों के बीच समाजवादी पार्टी की लोकप्रियता भी और बढ़ती जा रही है। नतीजतन विभिन्न दलों के कई नेता लगातार सपा में शामिल हो रहे हैं।

इसी कड़ी में दिनांक 16 जून 2021 को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में भरोसा करते हुए साहिबाबाद के पूर्व बसपा विधायक श्री अमरपाल शर्मा ने अपने सैकड़ों साथियों के साथ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। श्री अमर पाल शर्मा ने 2022 में श्री अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का पुनः मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया।

वहीं श्री अखिलेश यादव के अनुमोदन के पश्चात् सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश उत्तम पटेल ने नगर मंत्री भाजपा लखीमपुर खीरी रोहित तिवारी उर्फ लिटिल तथा भाजपा विधि प्रकोष्ठ के जिला मंत्री लखीमपुर श्री मनीष तिवारी को भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इनके आने से समाजवादी पार्टी को मजबूती मिलेगी।

श्री रोहित तिवारी उर्फ लिटिल तथा श्री

मनीष तिवारी ने श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व पर आस्था जताई है और सन् 2022 में समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार बनाने के लिए जी जान से जुटने का विश्वास दिलाया है।

वहीं गोरखपुर की भोजपुरी अभिनेत्री सुश्री काजल निषाद ने समाजवादी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर श्री अखिलेश यादव से भेंट की और शीघ्र ही समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेने की इच्छा जताई।

दिनांक 9 जून 2021 को पूर्व मंत्री और बबेरू, बांदा से भाजपा विधायक रहे श्री शिवशंकर सिंह पटेल अपने कई प्रमुख सहयोगियों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने उम्मीद जताई है कि इन साथियों के आने से समाजवादी पार्टी को मजबूती मिलेगी।

श्री शिवशंकर सिंह पटेल लगातार तीन बार बांदा जनपद के बबेरू विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे और उत्तर प्रदेश सरकार में सिंचाई एवं लोक निर्माण राज्यमंत्री भी रहे थे। श्री पटेल के साथ उनकी पत्नी श्रीमती कृष्णा पटेल, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत बांदा तथा भतीजे पूर्व ब्लाक प्रमुख श्री राजेंद्र सिंह ने भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इनके अतिरिक्त जिला पंचायत बांदा के सदस्य श्री अशरफ उल अमीन भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। इस अवसर पर सपा जिलाध्यक्ष बांदा श्री विजय करन यादव तथा भरत सिंह पूर्व सदस्य जिला पंचायत बांदा भी उपस्थित रहे।

दिनांक 17 जून 2021 को बसपा, भाजपा और कांग्रेस के कई प्रमुख नेताओं ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सभी ने सन् 2022 में समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार बनाने का संकल्प दुहराया। जनसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कांग्रेस नेता श्री दीपक कुमार अग्रवाल पिपराइच विधानसभा के सैकड़ों समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। उनके साथ शामिल होने वालों में प्रमुख रहे राम निवास उपाध्याय, कांतिप्रभा पत्नी रामकुमार, राम दयाल उर्फ शेरा जो बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए हैं। श्री मोहन गुप्ता कांग्रेस और त्रिभुवन गुप्ता भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए है।

इनके अलावा मोहम्मद अफरोज उर्फ गब्बर, नागेन्द्र सिंह और तमाम अन्य साथी भी समाजवादी पार्टी के सदस्य बने हैं। इस

अवसर पर समाजवादी पार्टी नेता श्री सुनील सिंह, जफर अमीन 'डक्कू' भी मौजूद थे। जनपद संत कबीरनगर की तहसील खलीलाबाद के गुप्ता वार्ड (7) से भाजपा समर्थित सभासद श्री त्रिभुवन कुमार गुप्ता ने भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और सन् 2022 के लक्ष्य को पूरा करने का संकल्प लिया।

इससे पहले दिनांक 7 जून 2021 को रामपुर मांझा जनपद गाजीपुर के जिला पंचायत सदस्य श्री अंकित भारती पुत्र श्री ओपी भारती ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। श्री अंकित भारती को समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाते हुए समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश उत्तम पटेल ने उम्मीद जताई है कि उनके आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। दिनांक 12 जून को समाजवादी पार्टी की नीतियों और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री

अखिलेश यादव के नेतृत्व पर आस्था जताते हुए राष्ट्रीय छात्र संगठन (कांग्रेस) (एनएसयूआई) के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर श्री जियाउल हक एडवोकेट ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस अवसर पर ऐडवोकेट राहुल यादव, नौमान आलम प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक सभा तथा फहद फैसल उपस्थित थे। जबकि वहीं दिनांक 11 जून 2021 को श्री कमलेश गुप्ता (हण्डिया विधानसभा, प्रयागराज) बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। इस अवसर पर सदस्य विधान परिषद श्री जगजीवन प्रसाद उपस्थित रहे।

चौधरी चरण सिंह
किसानों के सच्चे हितैषी

बुलेटिन ब्यूरो

समाजवादी पार्टी मुख्यालय सहित प्रदेश के प्रत्येक जनपद में दिनांक 29.05.2021 को पूर्व प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर सभी ने चौधरी साहब के बताए विचारों के रास्ते पर चलने का संकल्प

लिया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि चौधरी साहब की कृषि नीतियों से देश के अन्नदाता के जीवन का खुशहाल का रास्ता खुलता है। वे अर्थनीति के बड़े जानकार थे। उनका सम्पूर्ण राजनैतिक जीवन सादगी, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का उदाहरण है। भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए उनका जोर गांव-खेती और किसानों के उत्थान पर था।

चौधरी चरण सिंह जी आजीवन शोषित और समाज के वंचित लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कार्य करते रहे। उन्होने भूमि सुधार की दिशा में कई महत्वपूर्ण कानून बनाये। सार्वजनिक जीवन में व्यक्तिगत सम्पत्ति के आग्रह से वे जीवन भर दूर रहे। राजनीति में वे प्रकाश पुंज की तरह हैं। उनके बताए रास्ते पर चलकर ही समाज में समृद्धि और समरसता कायम की जा सकती है।

श्री यादव ने कहा कि चौधरी चरण सिंह जी आजीवन शोषित और समाज के वंचित लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कार्य करते रहे। उन्होने भूमि सुधार की दिशा में कई महत्वपूर्ण कानून बनाये। सार्वजनिक जीवन में व्यक्तिगत सम्पत्ति के आग्रह से वे जीवन भर दूर रहे। राजनीति में वे प्रकाश पुंज की तरह हैं। उनके बताए रास्ते पर चलकर ही समाज में समृद्धि और समरसता कायम की जा सकती है।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने चौधरी साहब के सपनों को तोड़ने का काम किया है। खेत-किसान-गांव कभी उसकी प्राथमिकता में नहीं रहे। किसानों की जमीन का जबरन अधिग्रहण कर उनको मजदूर बनाये जाने की साजिश की जा रही है। किसानों को फसल का लाभकारी दाम नहीं मिल रहा है। एमएसपी की अनिवार्यता से भाजपा मुंह चुरा रही है। उसको और ज्यादा प्रताड़ित करने के लिए तीन काले कृषि कानून भी थोप दिए गए हैं।

श्री यादव ने कहा कि चौधरी साहब ने सामंती व्यवस्था पर चोट की थी जबकि भाजपा खेती को उद्योग घरानों की बंधक बनाने पर तुल गई है। किसान इसको लेकर पिछले कई महीनों से आंदोलित हैं। सैकड़ों किसानों की धरना-प्रदर्शन में मौत हो गई। किसानों के दर्द के प्रति भाजपा सरकार पूरी तरह असंवेदनशील है। उनकी समस्याओं के समाधान के लिए यह अहंकारी भाजपा सरकार वार्ता करने तक को तैयार नहीं है इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा।

इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री सर्वश्री राजेंद्र चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी नरेश उत्तम पटेल, सदस्य विधान परिषद अरविन्द कुमार सिंह एवं डा. कुलदीप सक्सेना पूर्व अध्यक्ष आईएमए कानपुर ने भी श्रद्धासुमन अर्पित किए।

समाजवादी सरोकारों का अंग है पर्यावरण संरक्षण

बुलेटिन ब्यूरो

पर्यावरण संरक्षण के प्रति समाजवादी पार्टी हमेशा ही संवेदनशील रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार जब भी बनी उसने प्रदेश की हरियाली में इजाफा करने के अभियान को प्राथमिकता पर रखा है। समाजवादी सरकार के समय ही एशिया का सबसे बड़ा पार्क जनेश्वर मिश्र पार्क, गोमती रिवर फ्रंट, लोहिया पार्क बने जहां सुबह-शाम लोग खुली हवा में सांस लेते हैं और स्वास्थ्य लाभ करते हैं और जनता के आकर्षण के सबसे बड़े केंद्र हैं।

पर्यावरण संरक्षण के प्रति इसी प्रतिबद्धता के तहत समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष

भाजपा राज में बस कागजों पर ही वृक्षारोपण

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार जबसे सत्ता में आई है पर्यावरण को सबसे ज्यादा क्षति पहुंची है। वनसंपदा पर संकट के बादल मडरा रहे है और प्रकृति का असंतुलन बढ़ता गया है। फलतः वातावरण में गर्मी बढ़ रही है, तमाम उपयोगी संसाधनों का अभाव हो रहा है तथा ऋतु चक्र में भी बदलाव परिलक्षित हो रहा है।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार हर वर्ष वृक्षारोपण अभियान चलाती है लेकिन आज तक इस बात का ब्यौरा नहीं दे पाई है कि कहां कितने वृक्ष, किस वर्ष उसके शासनकाल में लगे। इनमे कितने पौधे बचे? वस्तुतः भाजपा सरकार ने पेड़ों की आड़ में बजट का बंदरबांट जमकर किया है। उसका ताजा दावा इस वर्ष 30 करोड़ पेड़ लगाने का है। 24 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में नए-पुराने हिसाब से तो हर घर में जंगल उग आना चाहिए। झूठ और नफरत के पौधे लगाने वाले भाजपाई पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करते हैं और उन्होंने वृक्षारोपण को मजाक बना दिया है।

पर्यावरण संरक्षण के बारे में भाजपा जहां झूठे दावे करती आई है और फाइलो में पेड़ उगाती रही है वहीं समाजवादी सरकार में पर्यावरण की दिशा में ठोस कदम उठाए गए थे। पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाए गए संकल्पित कदमों से प्रदेश का नाम देश-विदेश में ऊंचा हुआ। आज भाजपा राज में देश सांस लेने में भी संकट महसूस कर रहा है। कार्बन उत्सर्जन तथा प्रदूषण से बचाव के लिए समाजवादी सरकार में साइकिल सवारी को विशेष प्रोत्साहन देने हेतु साइकिल ट्रैक बनवाए गए। वहीं सुरक्षित और सुगम यातायात के लिए करोड़ों रुपए से लखनऊ एवं उन्नाव-शुक्लागंज में बने साइकिल ट्रैक को भाजपा ने राजनीतिक द्वेष से बर्बाद कर दिया।

खिलवाड़ की वजह से ही हम तमाम आपदाओं का न केवल सामना कर रहे हैं अपितु भावी संततियों के लिए मुसीबतें छोड़ने का भी काम कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हमें गंभीर प्रयास करने चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ नदियां पेड़-पौधे से सम्पन्न हरा पर्यावरण मिले।

इसी सोच के तहत समाजवादी पार्टी की सरकार में वृहद वृक्षारोपण का गिनीज बुक में विश्व रिकार्ड, बुंदेलखंड में जल संरक्षक तालाब एवं हरित पार्को का विकास किया गया।

पौधारोपण अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री सर्वश्री राजेंद्र चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, सदस्य विधान परिषदगण डा. राजपाल कश्यप, अरविन्द कुमार सिंह आदि उपस्थित रहे। पर्यावरण दिवस के अवसर पर श्री अखिलेश यादव को डा. आदित्य वर्मा की पुत्री सोनाक्षी वर्मा ने साइकोनियम, एयर प्यूरीफायर पौधा, अकरम उर्फ बब्लू और सुहागवती ने लीची का पेड़ भेंट किया।

एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने दिनांक 5 जून 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर समाजवादी पार्टी मुख्यालय लखनऊ के प्रांगण में हिमचंपा (मैगलोनिया) का पौधा रोपित किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि पृथ्वी के स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण संरक्षण अपरिहार्य है।

जैव विविधता में ह्रास और पर्यावरण के साथ

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हमें गंभीर प्रयास करने चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ नदियां पेड़-पौधे से सम्पन्न हरा पर्यावरण मिले।

साफ़ और बेबाक

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

Socialist Leader of India. Chief Minister of UP (2012 - 2017)

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

भारत के जाने-माने एथलीट एवं 'फ़्लाइंग सिख' के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह जी के कोरोना से निधन का दुःखद समाचार प्राप्त हुआ।

ईश्वर उनकी आत्मा को शांति व शोकाकुल परिजनों को यह दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें।

#MilkhaSingh

Translate Tweet

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

चिपको आंदोलन के प्रणेता, पर्यावरण संरक्षण के अग्रदूत एवं मशहूर पर्यावरणविद श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है।

ईश्वर पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दे। शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदना।

Translate Tweet

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

The BBC visited rural villages in UP, to get a true picture of the devastation left by COVID. The images and stories told by everyday people are heart wrenching. My deepest condolences to the families who lost loved ones.

bbc.co.uk
The 'unknown' Covid deaths in rural India

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

Fighting Covid isn't just a question about health, it's also about busting myths in our social media world. I want to thank all our front line rural health activists who are combatting COVID with facts and science!

theverge.com
India's healthcare workers are busting misinformation on WhatsApp

Akhilesh Yadav @yadavakhil... · 03 Jun

साइकिल चलती जाएगी,
आगे-आगे बढ़ती जाएगी।

'विश्व साइकिल दिवस' पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं...
साइकिल चलाएं... सेहत बनाएं... पर्यावरण बचाएं!

#WorldBicycleDay

Following

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

'भाजपा का छलावा' बहुत हुआ अब,
भाजपा को जनता सिखाएगी सबक!

आज सत्ताधारी सोच रहे हैं कि काश वो 'भ्रष्टाचार' का नाम बदल सकते और 'झूठ' के रंग भी। आज दुनियाभर की आस्थावान जनता अपने को ठगा महसूस कर रही है।

ये भाजपा का भावात्मक भ्रष्टाचार है।

#नहीं_चाहिए_भाजपा
#NoMoreBJP

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

जनाक्रोश को देखते हुए आख़िरकार सरकार ने कोरोना के टीके के राजनीतिकरण की जगह ये घोषणा करी कि वो टीके लगवाएगी।

हम भाजपा के टीके के ख़िलाफ़ थे पर 'भारत सरकार' के टीके का स्वागत करते हुए हम भी टीका लगवाएंगे व टीके की कमी से जो लोग लगवा नहीं सके थे उनसे भी लगवाने की अपील करते हैं।

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

व्यवस्था पर सवाल...

मीरजापुर में लालगंज ब्लाक के तिलांव गांव के गंभीर रूप से बीमार दर्द से कराहते 62 वर्षीय सतू मुसहर को चारपाई की डोली-खटोली बनाकर स्वजन उपचार के लिए आठ किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाये। स्वजन ने एंबुलेंस बुलाने का हर संभव प्रयास किया लेकिन मौके पर कोई सरकारी सहायता नहीं पहुंची। यहां तक कि गांव के प्रधान ने भी संज्ञान लेना मुनासिब नहीं समझा ● जागरण

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

हमने ही रखी बुनियाद... हम ही बाइस में करेंगे शुरुआत!

#सपा_का_काम_जनता_के_नाम

Translate Tweet

पंजीकृत डाक पंजीकरण संख्या GPO/LW/NP-300/2021-2023 कुल पृष्ठ : 40 डिस्पैच तिथि : 15, 16, 17

सबको वैक्सीन दूर की कौड़ी

समाजवादी पार्टी